respect of some units have been received. The matter is being processed for further necessary action.

Difference in Foreign investment policies

6437. SHRI V. RAJAN CHELLAPPA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have different policies for foreign investments made in India prior to 1989 and those made after 1990;

(b) whether it is a fact that policies are more favourable to foreign investment made after 1990;

(c) if so, the reasons for this discrimination;

(d) the steps proposed to be taken to reduce such discrimination; and

(e) whether there is any move to have an equitable foreign investment policy without regard to the year of investment?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI): (a) to (c): Government Foreign Investment Policy is governed by the Statement on Industrial Policy laid on the Table of the House on 24th July, 1991.

Under the policy, automatic approvals are being given by the RBI for foreign equity investment upto 51% in higher priority industries listed in Annex, III to the Statement. Other foreign investment proposals, outside the parameters for automatic clearance, are also considered and cleared on merits by the Government. Approvals for the foreign investment, in respect of specified consumer industries are also subject to the condition that remittance of dividends at foreign investment shall be balanced through export earnings.

These policy initiatives are aimed at attracting foreign investment and technology collaboration to obtain higher technology, increase exports and to expand the production base.

The present Foreign Investment Policy is not restricted to fresh proposals made after 24th July, 1991, but earlier approval holders or foreign investors can also take advantage of the new policy.

उत्तर प्रदेश में नए उद्योग स्थापित करने हेतु कार्यदल

6438. **श्री जनेश्वर मिश्र:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय उत्तर प्रदेश में औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों की संख्या कितनी है,

(ख) क्या सरकार ने औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों में नए उद्योगों की स्थापना या उनके विकास के लिए किसी कार्य-दल का गठन किया है, और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्यात्मक ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क): 70 वे दशक में की गई कार्यवाही के तहत उत्तर प्रदेश में 41 औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों का पता लगाया गया था।

(ख) और (ग): पिछड़े जिलों में नए उद्योग स्थापित करने अथवा इनका विकास करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा किसी कार्य-दल का गठन नहीं किया गया है। इन पहलुओं पर मुख्यतः राज्य सरकारों द्वारा विचार किया जाता है। केन्द्र सरकार परिवहन राज सहायता और करावकाश जैसी क्षेत्र विशेष के लिए विशिष्ठ सुविधाएं देकर इन प्रयासों में मदद करती है।

औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी०आई०एफ०आर०) की सिफारिश पर सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को बन्द किया जाना

6439. **श्री जनेश्वर मिश्र:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उन रूग्ण उपक्रमों को बन्द करना चाहती है जिन्हें औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने बन्द करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के इस निर्णय से इन उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे;

(ग) ऐसी स्थिति से निपटने के लिए क्या सरकार द्वारा कोई कार्यदल गठित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) से (घ) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल ने अभी तक संबद्ध उच्च न्यायालय को राष्ट्रीय साईकिल इण्डिया लिमिटेड, एल्गिन मिल्स कं० लिमिटेड, ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर टैक्सटाईल लिमिटेड और टैनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन लिमिटेड को बन्द करने की अनुशंसा की है। मामला सम्बन्धित उच्च न्यायालय में अनिर्णीत पड़ा हुआ है। कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए एक सुरक्षा तंत्र के रूप में राष्ट्रीय नवीकरण कोष स्थापित किया गया है। सरकार द्वारा किसी कार्यदल का गठन नहीं किया गया।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों हेतु सुविधाएं बढ़ाने की मांग

6440. **श्री जनेश्वर मिश्र:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को निजी क्षेत्र जैसी सुविधाएं दिए जाने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) क्या किसी सरकारी उपक्रम ने अपने उत्पादन क्षेत्र में विदेशी और निजी क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और इस पर सरकार की नीति क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) और (ख) सरकार को कोई विशिष्ट अभ्यावेदन/प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। बहरहाल, यदि कोई पृथक प्रस्ताव प्राप्त होता है तो गुणावगुण के आधार पर उस पर विचार किया जाएगा।

HEC, Ranchi

6441. SHRI DIPANKAR MUKHERJEE:
SHRI NILOTPAL BASU:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Heavy Engineering Corporation, Ranchi, has not been prequalified to bid for the 3rd Sinter Plant Project of Bhilai Steel Plant, even though the Project Report was prepared on the basis of the design and technology for identical plant built by H.E.C. for Visakhapatnam Steel Plant and that the last Sinter Machine of Bhilai Steel Plant was supplied/erected by H.E.C. on turn-key basis ahead of schedule;

(b) whether the use of one unit (Dip-Rail Circular Cooler) patented by a German Company has been made obligatory, thereby making this company and its licences the main bidders;

(c) whether the estimated price at the time of moving the proposal was much less than the present estimate; and

(d) if so, what action Government are taking in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Orders placed through Wagon India Ltd.

6442. SHRI DIPANKAR MUKHERJEE:
SHRIMATI CHANDRAKALA PANDEY:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the number of wagons (FWU) and the percentage thereof of the total wagons (FMU) that have been ordered for the year 1995-96 by Railway through Wagon India Ltd. (WIL);

(b) whether the above allotment through WIL is as per the prevailing practice followed so far;

(c) if not, the impact of the same on the wagon manufacturing industries under the purview of Wagon India Ltd. and the action taken by Government to ensure optimal utilisation of the capacities of the Wagon industry?